11 JULY 1952

(b) if so, what is the average amount contributed by the owner of the factory towards the Provident Fund of each labourer?

The Minister of Labour (Shri V. V. Giri): (a) and (b). No compulsory Provident Fund Scheme has been started by Government in glass factories in Uttar Pradesh. The Employees Provident Funds Act, 1952, which provides for the institution of provident funds for employees in factories and other establishments does not, for the present, apply to glass factories.

Ch. Raghubir Singh: May I know, Sir. whether the Government contemplate to start it in the near future?

Shri V. V. Giri: They do not contemplate it at present, but certainly they will be constantly examining this question.

Shri Nambiar: May I know. Sir, whether Government are proposing to ask the employers to contribute towards some gratuity or any other fund connected to the provident fund in view of the fact that there is no compulsory provident fund?

Shri V. V. Giri: That question does not arise out of this. I want notice.

Shri Velayudhan: May I know, Sir. whether the Government are contemplating a provident fund scheme for all these industries?

Shri V. V. Glri: It has already been stated to what industries this provident fund scheme applies.

पश्चिमी पाकिस्तान स्थित संपत्तियों के क्लेम

*१६७३, सेठ गोविन्द दास: (क)
क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा
करेंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान में
रह गयी संपत्तियों के लिये प्राप्त हुए
क्लेमों की राशि क्या है ?

- (स्त) बंगाल को छोड़ शेष भारत में निष्क्रमणार्थी संपत्तियों की कुल मत्य-राशि क्या है ?
- (ग) क्या पश्चिमी पाकिस्तान में रह जाने वाली संपत्तियों के मालिकों के

क्लेमों के भुगतान के लिये किसी योजना को अंतिम रूप दिया गया है ?

The Minister of Rehabilitation (Shri A. P. Jain): (a) Information cannot be supplied at this stage.

- (b) Valuation of evacuee properties is in progress and this information cannot be supplied.
- (c) The question of giving recompense to displaced persons for property left in West Pakistan is under consideration.

सेठ गोविन्द दास : क्या में यह जान सकता हूं कि यह हिसाब कितने दिनों से बन रहा है और इस के कब तक बन जाने की आशा की जा सकती है ?

श्री ए॰पी॰ जैन: यह हिसाब जनवरी सन् १९५१ से बन रहा है और में ने यहीं पर यह कहा था किं तीन महीने के अन्दर सितम्बर के आखिर तक बन जायगा।

पुनर्वास-व्यय

*१६७४. सेठ गोविन्द दास : क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के ऊपर १५ अगस्त १९४७ से ३१ मार्च १९५२ तक व्यय की गयी कुरू राशि क्या है; और

- (ख) निम्न राज्यों के तत्संवादी आंकड़े क्या हैं:
- (१) दिल्ली राज्य ; और
- (२) पंजाब राज्य ?

The Minister of Rehabilitation (Shri A. P. Jain): (a) Rs. 146.34 Crores.

- (b) (i) Rs. 13.64 Crores.
 - (ii) Rs. 24.86 Crores.

सेठ गोविन्द दास : सन् १९५२ के मार्च से लेकर सन् १९५३ के मार्च तक और कितना रुपया इस सम्बन्ध में खर्च करने का इरादा है ?